ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-11* December- 2020
Innovation The Research Concept

कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति एवं सरकार द्वारा उठाये गये कदम

The State of The Indian Economy in Corona Period And The Steps Taken By The Government

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 26/12/2020, Date of Publication: 27/12/2020

हंसराज
असिस्टेंट प्रोफेसर,
वाणिज्य संकाय
विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कैराना, शामली, उ0प्र0, भारत

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये कोरोना वायरस का अटैक हमारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत लेकर आया है। पिछले वर्ष की ही बात अगर हम करें तो रियल स्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, छोटे–छोटे उद्योगों सहित सभी असंगठित क्षेत्रों में मंदी छाई हुई थी, बैंक अपनी समस्या से निपटने में लगे थे, सरकार निवेश के जरिये नियमों में राहत और आर्थिक मदद देकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी बीच भारत में कोरोना वायरस आ गया और इसनें तो जैसे अर्थव्यवस्था का पहियां रोक दिया, ना ही कहीं पर उत्पादन हुआ और ना ही बाजारों में मांग रही, लोग घरों में बन्द हो गये और अपनी दुकानों पर भी सभी ने ताले लगाने पड़ गये।

इसके बाद सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोका जा सके और जिससे लोग अपने घरों में रहे तथा उचित दूरी का पालन होता रहे, जिससे वायरस कम से कम फैले। लॉकडाउन का ठीक से पालन करना कोरोना वायरस पर जीत तो दिला सकता है लेकिन इसने भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही अधिक बुरा प्रभाव डाल दिया है। अगर देखा जाये तो कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर पडा है। विश्व के बड़े–बड़े देश जैसे चीन और अमेरिका भी इस वायरस के सामने लाचार हो गये और इन देशों की अर्थव्यवस्था भी कोरोना वायरस की वजह से चौपट हो गई, इससे यह हुआ कि भारत में विदेशी निवेश के जरिये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिशों को भी धक्का लगा। जब विदेशी कम्पनियों के पास भी पैसे नही होगें तो वें निवेश में भी रूची नही दिखायेगीं। हालांकि जानकार बताते है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन सब स्थितियों का कितना गहरा असर पड़ेगा यह दो बातों पर निर्भर करेगा, पहली तो ये कि आने वाले समय में कोरोना वायरस की समस्या भारत में कितनी गम्भीर होती है और दूसरी बात यह कि इस समस्या पर कब तक काबू पाया जा सकेगा।

अतः यह कहना समीचीन होगा कि निकट व दूरगामी भविष्य में कोरोना त्रासदी किस सीमा तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगा और भारत सरकार इस भयंकर संकट से किस प्रकार आर्थिक मदद देकर भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारनें में अपना योगदान देगी।

Corona virus attack has brought a big trouble for the Indian economy. If we talk about the last year, then there was a slowdown in all the unorganized sectors including real estate, automobile sector, small industries, banks were dealing with their problems, the government would give relief to the rules through investment and giving financial help Was trying to push forward. But in the meantime, the corona virus came to India and it stopped the wheels of the economy, neither did it produce nor was there any demand in the markets, people closed their houses and everyone had to lock their shops. .

After this, the government announced a lockdown so that the infection of the corona virus could be prevented and people would stay in their homes and follow the proper distance, thereby spreading the virus to a minimum. Properly following the lockdown may win over the corona virus, but it has severely affected India's economy. If seen, the effect of corona virus has affected the whole world. The big countries of the world like China and America also got helpless due to this virus and the economy of these countries was also hit due to Corona virus, due to this, efforts to strengthen the economy through foreign investment in India. Was also shocked. When foreign companies do not have money, they will not show interest in investment. However, experts say that how much these conditions will have an impact on the Indian economy will depend on two things, firstly, how serious is the problem of corona virus in India and secondly, when will this problem Can be controlled.

Therefore, it would be expedient to say the extent to which the Corona tragedy will impact the Indian economy in the near and far future and how the Indian government will contribute towards the recovery of the Indian economy by providing financial help from this terrible crisis.

मुख्य शब्द : कोरोना वायरस, भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक सहायता।
Corona virus, Indian economy, financial aid.

प्रस्तावना

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 24 मार्च 2020 दिन मंगलवार रात 8 बजे देश को सम्बोधित करते हुए पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसमे जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सेवायें बन्द कर दी गयी, सभी कारोबार रूक गये, दुकानें बन्द हो गई और आवाजाही पर रोक लगा दी गई।

पहले से दिक्कत झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये कोरोना वायरस का अटैक हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया, पिछले वर्ष की ही बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल स्टेट, छोटे उद्योगों सहित असंगठित क्षेत्रों में मन्दी छाई हुई थी, बैंक एन पी ए की समस्या से निपटने में लगे थे, सरकार निवेश के जरिये नियमों में राहत और आर्थिक मदद देकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी बीच कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए हालात ने जैसे अर्थव्यवस्था का पहियां जाम कर दिया था, ना तो कहीं उत्पादन हुआ और ना ही मांग, लोग घरों में बन्द हो गये और दुकानों पर ताले लग गये थे।

एक अप्रैल 2020 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सी के द्वारा लगाया गया था लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उत्पादन और मांग की स्थिति को देखते हुए इस वृद्धि दर को भी घटाकर इस एजेन्सी के द्वारा 5.2 प्रतिशत कर दिया गया है, इसके साथ ही अगले वित्तीय वर्ष जो कि हमारा एक अप्रैल 2021 से प्रारम्भ होगा उसके लिए भी इस एजेन्सी ने हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 6.9 प्रतिशत की वृद्धि होना बताया है जब कि इस वायरस के फैलने से पहले का अनुमान अधिक था।

हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा इसलिए की थी जिससे कि इस वायरस को रोका जा सके। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा था कि सभी लोग अपने घरों के अन्दर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखे जिससे कि कोरोना वायरस कम फैले। हमारा मानना यह है कि लोग लॉकडाउन का ठीक से पालन करेंगें तो यह तो सम्भव है कि कोरोना वायरस कम फैलेगा लेकिन इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बडा संकट गहरा जायेगा, सब कारोबार आदि ठप हो जायेगें।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य वैश्विक त्रासदी के रूप में विद्यमान संकट से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा करना तथा भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को उबारने हेतु किये गये विविध प्रयासों को समग्र रूप से प्रस्तुत करना है। शोध–पत्र में विवेचना का मुख्य बिन्दु कोरोना संकट में आम आदमी से लेकर राज्य व केन्द्र सरकारों पर हुए आर्थिक प्रभावों को दर्शाया गया है, साथ ही केन्द्र सरकार की नीतियों का निरूपण आर्थिक पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

रूका कारोबार एवं रूकी अर्थव्यवस्था

हम जानते है कि हमारी अर्थव्यवस्था में 50 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद असंगठित क्षेत्रों से ही आता है, यह भी तय है कि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर इन्ही असंगठित क्षेत्रों पर पड़ने वाला है क्यो कि इनसे सम्बन्धित लोग काम नही कर पायेंगें, वे कच्चा माल भी नही खरीद पायेगें और अपना उत्पाद बाजार बन्द होने के कारण बेच भी नही सकते। हमारे भारत देश में छोटे–छोटे कारखानें एवं लघु उद्योगों की बहुत बड़ी संख्या है, सब कुछ बन्द होने के कारण इनका उत्पाद बाजार में नही बिक सकता तो फिर इनके सामनें तो धन की समस्या आयेगी, इनमें से बहुत ऐसे है जो कि बैंकों से कर्ज भी नही लेते है बल्कि इधर उधर कही से कर्ज ले लेते है जिसकी ब्याज दर बहुत ऊँचीं होती है। इस तरह ये सब कारखानें बन्द होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बडा धक्का पहुँचेगा।

लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बन्द रहेगें, वे कम्पनियों आदि में काम नही कर पायेगें, काम न होने से अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगना तय है। जब लोग घर ही रहते है तो इससे टैक्सी व्यापार, होटल व्यापार, रेस्टोरेन्ट, फिल्म उद्योग आदि सब पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जब लोग घरों से बाहर निकलते है तो उन्हे टैक्सी, रिक्शा आदि की सबसे ज्यादा जरूरत पडती है, लॉकडाउन के कारण ये व्यापार तो बिल्कुल बन्द हो जायेगा, ये अलग बात है कि लोग घर के प्रयोग की वस्तुएँ तो अवश्य ही खरीदेगें जैसे चावल, गेहूँ, सब्जी, आटा, लेकिन जो बडी वस्तुएँ है जैसे कार, टी वी, ए सी आदि, इनका खरीदना बेचना तो बिल्कुल बन्द हो जायेगा, इसका एक बडा कारण यह भी है कि लोगों के दिमाग में यह डर बैठ जायेगा कि कोरोना की इस त्रासदी में या तो उनकी नौकरी जायेगी या फिर उनका वेतन नियोक्ता द्वारा 50 प्रतिशत कम कर दिया जायेगा, इस वजह से भी लोग धन खर्च करना बन्द कर देगें।

कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र

लॉकडाउन और कोरोना काल की इस अवधि में सबसे ज्यादा असर पर्यटन, टैक्सी व्यापार, होटल, रेलगाडी, और हवाई जहाज की कम्पनियों पर पडने वाला है क्यो कि लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में रहेगें, कोई बाहर ही नही निकलेगा तो ये सब व्यापार चल ही नही सकते। हम अगर यातायात के साधनों की ही बात करें तो इन सबकी कमाई जब ही तो होगी जब लोग इन यातायात के साधनों का प्रयोग करेगें। रेलगाडियां भी बन्द कर दी गई है और अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं पर भी रोक लगा दी गई है। हवाई जहाज की कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन तो कम्पनी को चुकाना ही है भले ही वेतन 50 प्रतिशत कम क्यो न कर दिया जाये, जब हवाई जहाज उडेगें ही नही तो कमाई कैसे होगी। यही बात पर्यटन उद्योग पर भी लागू होती है, जब लोग घरों से ही नही निकलेगें तो घूमेंगें फिरेंगें कैसे, कोरोना

काल के इस भयंकर समय में लोग तो अब विदेश जाने में भी घबरायेगें और सबसे बडी बात यह है कि लॉकडाउन की इस अवधि में बच्चों की भी छुट्टियां है लेकिन लोग फिर भी कही भी घूमनें नही जा सकते, इस कारण पर्यटन उद्योगों की कमाई पर भी इस लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पडने वाला है।

इसके साथ ही यहॉ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि इस कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लग जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों, मजदूरों की एक बहुत बडी संख्या जो कि शहरों में जाकर बस गई थी तथा वहॉ पर उद्योग धंधे सब कुछ बन्द हो जाने के कारण ये लोग फिर से अपनें अपनें गांव लौट आये जिससे कि इन सबके सामने भी रोजगाार की एक बडी समस्या आ खडी हुई है।

लॉकडाउन के कारण नौकरियां भी खतरे में

कोरोना वायरस की यह बीमारी हमारे लिए केवल एक स्वास्थ्य संकट ही नही बल्कि यह एक बहुत बडा आर्थिक संकट भी बन गया है जो आम लोगों को बहुत बडे पैमाने पर प्रभावित करेगा। कोरोना वायरस की महामारी के कारण नौकरियां खत्म होने का अनुमान बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र की श्रम इकाई आई एल ओ के एक पूर्वानुमान के अनुसार अप्रैल 2020 से जून 2020 तक अर्थात तीन महीनें में ही लगभग 30.5 करोड़ लोगों की नौकरियां खत्म हो सकती है। जो क्षेत्र इस बुरे दौर से सबसे ज्यादा प्रभावित है उन्ही क्षेत्रों में ही नौकरियों को सबसे ज्यादा खतरा है। पर्यटन, होटल आदि सभी बन्द है, लॉकडाउन के कारण फैक्ट्ररी बन्द हो गई, जिससे कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की नौंकरियों पर खतरा मंडरा गया है। लोग ना तो घूमने निकल रहे और ना ही कोई नया सामान खरीद रहे है जब कि कम्पनियों के मालिक, होटलों के मालिक इन सभी को वेतन एवं अन्य खर्चो का भुगतान तो करना ही है, ये नुकसान झेल रही कम्पनियां, होटल ज्यादा समय तक भार सहन नही कर पायेंगीं तो फिर ये कम्पनियां कर्मचारियों को हटाना शुरू कर देंगी। हालांकि सरकार ने कम्पनियों से कर्मचारियों की नौकरी खत्म न करने को कहा है लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर पडता प्रतीत नही होता है। कोरोना वायरस फैलने के साथ साथ यह खबरें भी लगातार आ रही है कि लाखों कर्मचारियों को नौंकरियों से निकाल दिया गया है या बिना वेतन के लम्बी छुटटी दे दी है अथवा वेतन में भारी कटौती कर ली गई है। इसके अलावा जो लोग अपने खुद के रोजगार में लगे थे या छोटे मोटे काम धंधे करके अपने परिवार को किसी तरह पालते थे उनकी भी आय का कोई जरिया नही रहा। लॉकडाउन के कारण जिन व्यक्तियों की नौकरी एक दम से खत्म हो गई अथवा उनका स्वयं का रोजगार अचानक से बंद हो गया उन्हें धन की परेशानी के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक चुनौंतियों का भी सामना करना पड़ रहा है यह उन सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका है।

कोरोना काल में लॉकडाउन एवं 2008 की मंदी की तुलना

हमने 2008 की मंदी का दौर भी देखा था जब कई कम्पनी बन्द हो गई थी जिसके कारण बहुत लोगों का रोजगार खत्म हो गया था। तो क्या यह कोराना वायरस का संकट 2008 की मंदी से भी खतरनाक है ? इसके सम्बन्ध में हमे यह ध्यान रखना चाहिये कि 2008 की मंदी के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी प्रभावित नही हुई थी, हम यह भी जानते है कि 2008 में मनरेगा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मनरेगा की सक्रियता की वजह से लगभग 6 महीनें में ही भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी थी, लेकिन कोरोना वायरस के फैलने के डर से अभी तो हम एकजुट होकर काम भी नही कर सकते है।

यह तो हमने देखा ही है कि लॉकडाउन की वजह से गांव से जो मजदूर पहले काम की वजह से शहरों मे चले गये थे अब बडी संख्या में वे मजदूर फिर अपने गांव पहुॅच चुके है, सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने की वजह से गांव में भी कामकाज बन्द है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने कुछ शर्तो के साथ मनरेगा के तहत काम करने की छूट दे दी है इसमें उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। लॉकडाउन लगने के बाद गांव में मनरेगा ही एक रोजगार का साधन बचा है। सरकार मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को कई तरह के काम दे सकती है। वही इस त्रासदी के बीच सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले व्यक्तियों की मजदूरी बढा दी है। मनरेगा में मजदूरों को पहले 182 रूपये प्रतिदिन मिलता था जिसको बढाकर 202 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है।

अतः हम यह कह सकते है कि कोरोना का यह समय 2008 की मंदी से भी ज्यादा बुरा है क्यो कि 2008 की मंदी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित नही हुई थी, अब गांव में हालात यह है कि वहॉ पर जितने मजदूरों की आवश्यकता है उससे कई गुना मजदूर वहॉ मौजूद है क्यों कि शहरों में उद्योग धंधे बन्द है जिस कारण सभी मजदूर अपने गांव पहुॅच गये।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोरोना वायरस की महामारी से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, मोदी जी ने इस आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही कहा था कि इस पैकेज से देश के विभिन्न वर्गो को सहायता मिलेगी और यह "आत्मनिर्भर भारत अभियान" को नई गति देगा।

इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच ब्रीफिंग में 20 लाख करोड़ रूपये का लेखा जोखा दिया कि किन–किन मदों में कितनी राशि खर्च की जायेगी। पहली ब्रीफिंग में उन्होनें 5.94 लाख करोड़ रूपये की रकम मुख्य तौर पर छोटे व्यवसायों को कर्ज देने और गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और बिजली वितरण कम्पनियों की मदद के नाम पर आबंटित करने की घोषणा की। दूसरी ब्रीफिंग में उन्होनें 3.10 लाख करोड़ रूपये प्रवासी मजदूरों को दो महिने तक मुफ्त में अनाज देने और किसानों को कर्ज देने में प्रयोग करने की बात कही। तीसरी ब्रीफिंग में वित्त मंत्री जी ने 1.5 लाख करोड़ रूपये खेती के बुनियादी ढांचे को ठीक करने और कृषि से जुडे सम्बन्धित क्षेत्रों पर खर्च करने की बात बोली। शेष

धनराशि चौथी और पांचवीं ब्रीफिंग में कोयला क्षेत्र, खनन, विमानन, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर शिक्षा, रोजगार, व्यवसायों की मदद और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सुधार की बात कही। वित्त मंत्री की यें घोषणायें क्या वास्तव में कोई राहत देंगी और इस त्रासदी में प्रभावित हुए व्यक्तियों को कोई राहत प्रदान करेंगी।

बैंकों का एन पी ए–

भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जो 20 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है उसमे ज्यादातर घोषनायें कर्ज देने की शक्ल में है। सरकार यह मानती है कि जब व्यावसायों को कर्ज दिया जायेगा तो वे अच्छे से चलेगें और फिर उनसे रोजगार पैदा होगा। लेकिन यहॉ पर यह ध्यान रखने की बात है कि अगर बैंक कर्ज देते गये तो क्या उनका एन पी ए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) बहुत अधिक बढ़ नही जायेगा ? भारतीय रिजर्व बैंक ने तो यहॉ तक कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी से पैदा हुए इस आर्थिक संकट से बैंकों का एन पी ए पिछले 20 वर्षो में सबसे ऊपर जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि मार्च 2020 में जो एन पी ए 8.5 प्रतिशत था वह मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत पर पहुंच सकता है । इसलिए समस्या अब यह है कि अब अगर ऋण दिये जायेगें तो फिर इनका एन पी ए और ज्यादा बढने की गुंजाइश हो जायेगी। दूसरी और सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जब बाजार में मांग ही नही है तो फिर व्यावसायों के मालिक ऋण क्यों लेगें। अतः सरकार को बाजार में मांग बढाने के उपाय सोचनें चाहिए।

निष्कर्ष

कोरोना त्रासदी के इस काल में लॉकडाउन की वजह से चरमरा रही भारत की अर्थव्यवस्था एवं भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदम नामक इस शोध पत्र में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचें है कि कोरोना वायरस का यह समय बहुत भयंकर है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो छोटे मोटे काम करके अपने परिवार को चलाते है और जो मजदूर वर्ग गांव से निकल कर शहरों की तरफ चले गये थे उन्हें वापिस अपने गांव आना पडा। सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है वह भी नाकाफी है और उसका तरीका भी पूरी तरह सही नही है। मार्च 2020 से अब तक गरीबों के लिए जो घोषणायें हुई है उसमें 31000 करोड़ रूपये तो जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक खातों में भेजने की बात कही गई थी, 3000 करोड़ रूपये वृद्धा पेंशन में देने की बात कही गई थी, इसमें अब 40000 करोड़ रूपये मनरेगा के लिए और जोडा गया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें तीन महीनों तक दोगुना राशन दिया जायेगा और फिर इसमें 8 करोड़ और लोगों को जोडा गया लेकिन सिर्फ दो महीनों के लिए। गरीबों के लिए तो बस इतनी ही घोषनायें हुई है जो कि बहुत कम है, और ये सब मिलाकर जी डी पी का एक प्रतिशत भी नही है। भारत सरकार ने तुरन्त राहत देने वाले कदम ना के बराबर उठायें है, इसी बात की तुलना अगर हम दूसरे देशों से करे तो यह बेहद कम है। गरीबों को दोगुना राशन दिये जाने के फैसले को और तीन या चार महीनों तक किये जाने की आवश्यकता थी। सरकार के पास गेंहूँ और चावल का स्टॉक बहुत है जितना स्टॉक होना चाहिए उसका तीन गुना अनाज पडा हुआ है। इस आर्थिक पैकेज में सरकार द्धारा की गई ज्यादातर घोषनायें कर्ज देने की शक्ल में है। कर्ज देने की इन घोषनाओं से गरीब लोगों को तो कोई लाभ होने वाला नही है, लघु और मध्यम उद्योग कर्ज भी जब ही लेगें जब उन्हें लगेगा कि वे अपना व्यवसाय 6 महिने पहले के स्तर पर ले जा सकते है, जब उन्हें पता है कि बाजार में मांग ही नही है तो वे कर्ज क्यों लेंगें। सरकार ने इन उद्योगों को कर्ज देने के लिए 3 लाख करोड़ रूपये की घोषणा की है जिसकी सीमा अक्टूबर तक समाप्त हो जायेगी। सरकार की जो भी घोषनायें है इसमे वित्तीय प्रोत्साहन बहुत कम या फिर ना के बराबर है, इससे बाजार में सुधार नही आयेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *दैनिक अमर उजाला, मेरठ संस्करण*
2. *https://www.bbc.com/hindi/india-52028430*
3. *पत्रिका (ऑनलाइन वर्चुअल राष्ट्रीय समाचार एजेन्सी)*
4. *बी बी सी न्यूज हिन्दी*
5. *www.bbc.com/hindi/india-52700326*
6. *m.economictimes.com*